

मणिपुर : एन.पी.पी. ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया

फिलहाल सरकार को खतरा नहीं है क्योंकि 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 32 सदस्य हैं

इंफाल/आइजोल, 17 नवंबर। मणिपुर में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद से हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार में शामिल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान किया है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में नेशनल पीपुल्स पार्टी के 7 सदस्य हैं, जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा के पास 32 सदस्य हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। ऐसे में सरकार को फिलहाल खतरा नहीं है।

कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (एन.पी.पी.) ने राज्य में मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पार्टी ने कहा कि संकट से निपटने के तरीके और निर्दोष लोगों की जान जाने से असंतुष्ट होकर उन्होंने तत्काल प्रभाव से सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है।

एन.पी.पी. द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, "हमें दृढ़ता से लगता है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर राज्य सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है।

■ नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापस लेने वाले पत्र में कहा कि मणिपुर की राज्य सरकार संकट को हल करने व राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है।

वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की हुई है। यहां पिछले साल मई के महीने से मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष चल रहा है, जो एक बार फिर हिंसक रूप ले चुका है। तीन बच्चों और तीन महिलाओं की मौत के बाद से यहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की चार रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए हैं। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करेंगे। वहीं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा जा रहा है।

राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल

विशेषाधिकार अधिनियम वापस लेने को कहा है। हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिस्नुपुर जिलों के सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लोमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना इलाकों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लगाया था।

ज्ञातव्य है कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और 10 विधायकों के घरों पर हमले हुए। हालात बिगड़ने के बाद से 5 जिलों में कर्फ्यू और 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद है।

कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने बीरेन सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है। सूत्रों के अनुसार अगले दो-तीन दिनों में हालात और बिगड़े तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू सकता है।

ज्ञातव्य है कि शनिवार 16 नवंबर

को जिरीबाम में बराक नदी के तट से दो महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। शक है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अपहृत किया था। ग्यारह नवंबर को ही सुरक्षाबलों ने 10 बंदूकधारी उग्रवादियों को मार डाला था। जबकि कुकी-जो संगठन ने इन 10 लोगों को विलेज गाड़ बताया था। प्रह्रं नवंबर की रात भी एक महिला और दो बच्चों के शव मिले थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर में आपकी (भाजपा की) डबल इंजन सरकार है। ना मणिपुर एक है, ना मणिपुर सेफ है। मई 2023 से यह अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है।

विरोध प्रदर्शन के चलते मणिपुर के पांच घाटी जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि सात जिलों में शनिवार शाम 5:15 बजे से दो दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये जिले हैं- इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर।

गृह मंत्री शाह ने मणिपुर की समीक्षा की

नई दिल्ली, 17 नवंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की तथा शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया।

सूत्रों ने जानकारी दी। अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करके लौटने के तुरंत बाद यह बैठक की।

■ अमित शाह ने राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिये हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिये।

सूत्रों के अनुसार शाह आगे के कदमों पर सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक और विस्तृत बैठक करेंगे।

सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध-प्रदर्शन और हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मणिपुर पिछले साल मई से ही जातीय संघर्ष से जूझ रहा है।

शिमला के रामकृष्ण मंदिर पर विवाद खड़ा हुआ

शिमला, 17 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में संजीली मस्जिद विवाद के बाद अब शिमला में राम कृष्ण मिशन मंदिर पर विवाद शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि मंदिर पर कब्जा करने के लिए शनिवार देर रात एक बजे के आस-पास ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच जमकर मारपीट तोड़फोड़ और पथराव हुआ। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी हुई नजर आई। पथराव में आघात दर्जन से अधिक लोग घायल हुए

■ शनिवार रात एक बजे ब्रह्मो समाज तथा रामकृष्ण मिशन के बीच कब्जे को लेकर मारपीट, तोड़फोड़ व पथराव हुआ।

है। पुलिस ने दो एफ.आई.आर. दर्ज की हैं जिसकी जांच जारी है। राम कृष्ण मिशन के लोगों का पक्ष है कि मंदिर का माली, कांग्रेस का एक नेता और कुछ अन्य लोग मंदिर पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि ब्रह्मो समाज ने 2014 से मंदिर धार्मिक कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन को दे रखा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचारार्थन है लेकिन कांग्रेस सरकार के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में दो नक्सली डिप्टी कमांडर मारे गए

कांकेड़ जिले के मुसफर्सी गाँव के नजदीक हुई मुठभेड़ में एक घंटे गोलीबारी हुई

कांकेर, 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कांकेर जिले के पखांजुर थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बड़े कैडर के माओवादी मारे गए। यह मुठभेड़ जिले के मुसफर्सी कांकर गाँव के नजदीक हुई, जहां दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक गोलीबारी चलती रही।

मारे गए नक्सलियों की पहचान रंजीत और संतोष के रूप में हुई है, जो डिप्टी कमांडर रैंक के थे। इस मुठभेड़ को भी सुरक्षा बलों की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

शनिवार को हुई मुठभेड़ के बाद जवान माड़ इलाके में सर्च कर रहे थे। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों का एक बड़ा गुप्त देर रात मुसफर्सी के जंगल में छिपा हुआ था। मौका देखते हुए नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस ने पहले से सतर्क रहते हुए जवाबी कार्रवाई की,

मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने "आप" की परेशानी बढ़ाई

पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार के दो मंत्री व दो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं

नयी दिल्ली, 17 नवंबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा मंत्रिमंडल एवं आम आदमी पार्टी (आप) की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गहलोत ने आज इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने पत्र में इस्तीफा देने की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करना बताया है।

उन्होंने पत्र में लिखा है, शीशमहल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास "आप" से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ।

■ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने त्यागपत्र में यमुना की सफाई तथा केजरीवाल के "शीश महल" के विवादों पर सवाल उठाया है।

■ आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि गहलोत के ऊपर ई.डी., आयकर सहित तमाम तरीके के दबाव थे।

गौरतलब है कि, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार के दो मंत्री और दो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री आतिशी व केजरीवाल को लिखे पत्र में मंत्री पद छोड़ने के कारणों में यमुना की सफाई और नए बंगले के विवाद की बात भी कही। वहीं मुख्यमंत्री ने बिना विलंब गहलोत के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि, दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में प्रस्तावित हैं। इससे पहले गहलोत ने एकाएक पार्टी छोड़ने से कई सवाल उठ रहे हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में

जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि कैलाश गहलोत का मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गंदी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को कहा कि आज भाजपा एक बार फिर अपने हथकंडे, धिनीनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। गहलोत के ऊपर लगातार भाजपा द्वारा दबाव बनाया जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री ने "द साबरमती रिपोर्ट" फिल्म की प्रशंसा की

नई दिल्ली, 17 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 के गोधरा कांड पर बनी फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" की तारीफ की है। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है, और वह भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें। एक फजी कदानी सीमित समय तक ही चल सकती है। आखिरकार, सच हमेशा सामने आते हैं! प्रधानमंत्री ने विक्रान्त मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा सहित अन्य

■ यह फिल्म गोधरा कांड पर बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी की।

कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म की प्रशंसा करते हुए यह टिप्पणी एक एक्स यूजर की फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए की। यूजर ने अपनी समीक्षा में कहा इस फिल्म को जरूर देखें। यूजर ने कहा कि निर्माताओं ने 2002 के गोधरा कांड के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए सराहनीय काम किया है। गोधरा कांड में महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों की जान चली गई थी। "द साबरमती रिपोर्ट" का निर्देशन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में सोमवार को मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली, 17 नवंबर। मौसम विभाग ने सोमवार (18 नवंबर) के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार सोमवार को दिल्ली में घना कोहरा पड़ सकता है। वहीं, लगातार खराब होती हवा के चलते सोमवार (18 नवंबर) से दिल्ली में ग्रेप-4 लागू करने का फैसला किया गया

■ उत्तरी राज्यों में बर्फबारी से दिल्ली में ठंड बढ़ेगी, घना कोहरा पड़ सकता है।

है। इसके साथ ही दिल्ली में ठंड बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। उत्तरी राज्यों में बर्फबारी हो रही है और रविवार रात नोएडा में तेज हवाएं चल रही हैं। इससे साफ है कि आज आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने लम्बी दूरी की हाइपरसॉनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया

यह मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जा सकती है

नयी दिल्ली, 17 नवंबर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लंबी दूरी की पहली हाइपरसॉनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि यह परीक्षण शनिवार को देर रात ओडिशा के तट पर डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस हाइपरसॉनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।

मिसाइल को विभिन्न डोमेन में तेनात विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया था। उड़ान डेटा ने सफल टर्मिनल युद्धम्यास और उच्च

अमृतसर में तस्करी के हथियार व मादक पदार्थ बरामद

अमृतसर, 17 नवंबर। अमृतसर कमिश्नरेंट पुलिस ने सीमा पार से हो रही मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के कार्टेल का भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.5 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम मेथाक्वालोन पाउडर और दो पिस्तौल

■ अमृतसर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।

समेत एक अत्याधुनिक 9एमएम रॉलक बरामद किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान वंश उर्फ बिल्ला (23), निवासी बिल्ले वाला चौक, अमृतसर, और सोनू चौरसिया (20), निवासी दशमेश नगर, अमृतसर, के रूप में हुई है। इस संबंधी मामले में थाना मोहकमपुरा में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

गढ़ चिरोली, 17 नवंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आयोजित चुनावी सभाओं के दौरान दिए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के, "एक हैं तो सुरक्षित हैं" नारे की आलोचना करते हुए रविवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वाड़ा ने कहा कि एक दशक के शासनकाल में देश में किसान हो, मजदूर हो, महिला हो या युवा, अगर कोई सुरक्षित है तो वह सिर्फ उद्योगपति गौतम अडानी हैं।

प्रियंका ने कांग्रेस-महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एम.वी.ए.) उम्मेदवारों के लिए आयोजित एक चुनावी सभा में जनता से अपील की कि वे विधानसभा चुनाव में सावधानी से

मतदान करें और ऐसी सरकार चुनें जो जनता के हित में काम करे, उद्योगपतियों के हित में नहीं। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हित को देखकर विभिन्न राज्यों में बड़े-बड़े संस्थान, कारखाने, बंदरगाह, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल स्थापित किए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी विकास कार्यों में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन पिछले 11 वर्षों से देश

में भेदभाव की राजनीति चल रही है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में आने वाली बड़ी परियोजनाओं को गुजरात और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भेजकर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया है। नतीजतन, महाराष्ट्र में बेरोजगारी बढ़

उन्होंने यह बात चुनाव सभा में भाजपा के नारे, "एक हैं तो सुरक्षित हैं" की प्रतिक्रिया में कही

■ प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी के एक दशक के शासनकाल में किसान, मजदूर, महिला या युवा, कोई भी सुरक्षित नहीं है, केवल उद्योगपति गौतम अडानी सुरक्षित हैं।

गई है, यहां तक कि 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। उन्होंने बताया कि अनुबंध के आधार पर भी भर्ती की जा रही है। इसके अलावा देश के सभी हवाई अड्डे, बंदरगाह, कारखाने, जमीनें एक उद्योगपति को दे दी गई हैं। इसके

अलावा, राज्य में किसान मुसीबत में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कृषि उपज की कीमत नहीं मिल रही है, उन्होंने बताया कि कपास और सोयाबीन की कीमतें पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़ी हैं। वाड़ा ने कहा कि इसके विपरीत, पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सोयाबीन की कीमत 7,000-8,000 रुपये थी, जो आज केवल 4,000 रुपये है। इसी तरह प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण 50 लाख टन प्याज बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय नहीं

बढ़ रही है और कृषि आदानों पर जीएसटी लगाकर उन्हें लूटा जा रहा है। आदिवासियों की बात करते हुए वाड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पेसा कानून बनाया, इसके विपरीत आज भाजपा शासित राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र में चार लाख आदिवासियों ने भूमि पारसल के लिए आवेदन किया था, जिनमें से दो लाख के आवेदन खारिज कर दिए गए। इसी तरह देशभर में 22 लाख आदिवासियों के आवेदन खारिज कर दिए गए।

उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गठन की बैठक में उद्योगपति अडानी की मौजूदगी का जिक्र करते हुए मोदी और भाजपा पर राज्य सरकार चुराने का भी आरोप लगाया।